(ख) अब तक कोई भी युवा विकास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि यह एक नई योजना है, इसलिए योजना आयोग जैसे विभिन्न निकायों के सुझाव अपेक्षित है। तथापि, स्थायी वित्तीय समिति ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

छोटे शहरों में खेल कूद संबंधी बुनियादी सुविधाएं

2905. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल-कूद संबंधी बुनियादी सुविधाएं केवल बड़े-बड़े शहरों एवं कस्बों में ही संकेन्द्रित होती जा रही है और छोटे-छोटे शहरों एवं कस्बों की इस मामले में उपेक्षा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :
(क) जी, नहीं ।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय बड़े शहरों और छोटे शहरों/कस्बों में कोई विभेद नहीं करता है। खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान की योजना में वस्तुतः ग्रामीण, ब्लाक और जिला स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। तथापि, ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा समर्थित होना चाहिए और तत्पश्चात् स्थान का चयन अंततः राज्य सरकारों की सिफारिशों से ही होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Haryana Scheme to be Replicated Nationwide

2906. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: been drawn *to* the news-item which app-

(a) whether Government's attention has eared in the 'Indian Express' dated 23rd January, 1995 under the caption "Haryana Scheme to be replicated nationwide";

(b) if so, what are the full details in this regard; and

(c) what concrete and effective meas ures Government propose to take for launching the same scheme in all the States and Union Territories of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESH-WARI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached *(See* below).

(0) There is no proposal under consideration of Government of India *to* replicate the Haryana Scheme in all the States and Union Territories.

Statement

The State Government of Haryana has launched a new scheme of "Apni Beti Apna Dhan" in the State with effect from 2-10-1994. This Scheme aims at the upliftment of status of the girl child in society so as to bring a change in people's attitude to treat daughters as assets rather than as burdens. Scheduled Caste, families (except Class T and Class II officers and Income Tax paving families) and in case of other castes, families below the poverty line having a maximum of 3 children including new born are eligible. Under this schmee Rs. 500|- are erven to the mother for her nutrition within 15 days of giving birth to a girl child, and Rs. 250O/—. are invested in Indira Vikas Patras in the name of the girl child for a period of